के साथ लघु उद्योग खोले जाएं तो उनसे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सकेगा और स्थानीय लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिल सकेगा ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में समुचित कदम उठाये ।

(iv) NEED FOR EXTRA ALLOTMENT OF CEMENT TO ORISSA FOR WORKS TO CONTROL FLOODS.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Quarterly allocation of cement to Orissa has been reduced from 1,23.400 M.T. in the first quarter of 1980 to 81,400 M.T. in the fourth quarter of 1980. Several bridges and culverts were washed away. Most of the public and private buildings in the flood-affected areas were seriously damaged. For flood restoration work, at least *ad hoc* allocation of cement to Orissa is urgently needed. I urge upon the Government to direct the Cement Controlled to allot extra quantity of cement to Orissa urgently for flood restoration work, and not to curtail the allotment of cement to Orissa from the two cement factories of the State, as the landing cost of Andhra cement is much more at places like Puri and Cuttack.

(v) DRINKING WATER PROBLEMS OF PATNA CITY

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, "पटना में पेय जल संकट" । पटना नगर बिहार की राजधानी है । चल रहे जनगणना अभियान के बाद उसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो जाने का अनुमान है । शहर का विकास भी तेजी के साथ हो रहा है ।

नगर के विकास के साथ-साथ उसकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं जिनके निराकरण की ओर सरकार का ध्यान या तो आकृष्ट नहीं हो पा रहा है या धनाभाव के कारण वह कुछ कर सकने में असमर्थ है । समस्याओं में पेय जल का संकट सब से बड़ी समस्या है । नहाने-धोने की बात तो दूर रही पीने के लिए भी लोगों को पानी नहीं मिलता । गर्मी के दिनों में तो नागरिकों में कहराम्ब मच जाता है और लोगों को पानी की तलाश में दूर-दूर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पाता । कभी कभी तो विरोधस्वरूप घड़ा फोड़ो अभियान भी चल पड़ता है ।

बांकीपुर और पटना सिटी दोनों क्षेत्रों के दर्जनों मुहल्लों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है । इसका कारण आर्थिक है । धन के अभाव में बड़े बड़े नलकूप और टंकियों की व्यवस्था नहीं हो पाती । पटना वाटर बोर्ड ने इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार से साढ़े चार करोड़ रुपये की मांग की है । राज्य सरकार ने इसके लिए भारत सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है । मेरा अनुरोध होगा कि पटना नगर में जल की व्यवस्था के लिए सरकार को शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार को मदद भेजनी चाहिए ताकि पेय जल की उचित व्यवस्था की जा सके ।

(vi) NEED FOR STEPS FOR IMPLEMENTATION OF PALEKAR AWARD

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, पालेकर न्यायाधिकरण की घोषणा हो जाने के बावजूद भी अभी तक बड़े-बड़े अखबार उससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय काम में ला रहे हैं । अगर सरकार के द्वारा इसे अविलम्ब लागू करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में इनके लागू करने के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायेगी । संवाददाताओं के विभिन्न संगठनों ने भी इस प्रकार की मांग का समर्थन करते हुए त्रिपक्षीय समिति बनाने की मांग की है । जिसमें अखबार व समाचार एजेन्सियों के संवाददाताओं के प्रतिनिधि, अखबारों के प्रबंधक के प्रतिनिधि व केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों । जो पालेकर एवार्ड के न्यायसंगत क्रियान्वयन को देख सकें क्योंकि जब से इस एवार्ड की घोषणा हुई है बड़े बड़े अखबारों ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों में डालना प्रारम्भ कर दिया है। इसके शिकार विशेष रूप से अंशकालिक संवाददाता हो रहे हैं जो इन अखबारों में 20-25 वर्ष से कार्य करते आ रहे हैं ।

[श्री अशोक गहलोत]

यह आश्चर्य की बात है कि जब सरकार की तरफ से पालेकर एवार्ड लागू कर इन अनुभवी, परिश्रमी अंशकालीन संवाददाताओं को अपने जीवन पर्यन्त किये गये परिश्रम का प्रतिफल मिलने का प्रश्न तो अलग रहा, इन बड़े अखबारों के प्रबंधकों ने बिना कारण बताये ही इनकी छंटनी शुरू कर दी है। जिससे पूरे देश भर के दूर में बैठे अंशकालिक व अन्य संवाददाताओं में घोर निराशा व्याप्त हो रही है।

माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में अविलम्ब आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही प्रारंभ करें जिससे पालेकर एवार्ड के कारण बड़े अखबार के प्रबंधकों द्वारा अंशकालिक व अन्यों को निकालने की प्रक्रिया से रोका जा सके व उन्हें पुनः नियुक्ति दी जाकर उन को न्याय दिलाया जाये। जिनसे आने वाले समय में इस उद्योग में और भी प्रतिभावान लोग आकर्षित हो सकें।

(vii) TAX MARK PERMIT TO POWERLOOM WEAVERS OF BURHANPUR

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा): अध्यक्ष महोदय, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) के 150 परिवारों में निर्धारित समय के पश्चात टैक्सटाईल्स कमिश्नर बंबई को टैक्स मार्क परमिट (पावरलूम) के लिए आवेदन देने से उन्हें टैक्स मार्क परमिट नहीं मिला है। स्थानीय सेंट्रल एक्साइज अधिकारी पावरलूम नहीं चलाने दे रहे हैं। पावरलूम वाले गरीब हैं और कर्ज में दबे हुए हैं। उनके पावरलूम बिकने की नौबत आ गई है। वे भयभीत हैं अतः वित्त मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री महोदय राहत पहुंचाएं, यह निवेदन है।

(viii) NEED FOR EARLY DECISION ABOUT SETTING UP OF A REGIONAL RURAL BANK IN SAGWARA TOWN IN RAJASTHAN.

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara): I want to re-emphasize my earlier submission regarding opening of a branch of Regional Rural Bank in my constituency at Sagwara in Rajasthan. The area is backward area and mainly inhabited by Scheduled Tribes. Though this area has abundance of cash crops growing areas and growing ground-nut in sufficient quantity, banking facilities are negligible. Population of the Sagwara town is also 15,000 and would cater well for any banking venture of rural charter. Moreover, this would give a much needed fillip to the existing small scale units in the town. Even the rural and traditional craftsmen would benefit by such a bank branch.

I would, therefore, request Minister of Finance to take an Immediate decision in the matter.

(ix) ALLEGED RECOVERY OF DEFENCE ARMAMENTS IN AGRA

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आगरा में 24 फरवरी को मोती कटरा में एक गोदाम में सेना के बम विस्फोट के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, कई व्यक्ति घायल हुए, जिनकी स्थिति शोचनीय है। जांच के दौरान सेना के शक्तिशाली बम, विस्फोटक पदार्थ, बंदूकों रायफलों के पुर्जे, एयर फोर्स, नेवी और थल सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री, कई क्विंटल राकेट, 84 बोरों में रखे हुए बमों तथा अन्य रक्षा सामग्री आदि बरामद हुए हैं। ये सामान अब भी मोती कटरा की घनी वाली आबादी वाले इलाके में पड़ा हुआ है। जन-जीवन को इससे भारी खतरा पैदा हो गया है। रक्षा सामग्री की चोरी में रक्षा कर्मचारियों के भी हाथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सरकार से निवेदन है कि इन बमों को घनी आबादी से हटाकर किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोके एवं इसकी जांच कर सदन के सज्ञान में लाएं।

(x) NEED FOR STEPS TO AVOID STRIKE BY JUNIOR DOCTORS OF DELHI

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के साथ किए गए समझौते